

प्रेषक,

डी० पी० गैरोला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
लोक सेवा अधिकरण, उत्तराखण्ड
316- फैंज-II, वसन्त विहार,
देहरादून।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 22 फरवरी, 2013

विषय— लोक सेवा अधिकरण, उत्तराखण्ड देहरादून में संयुक्त निबन्धक (सिविल जज, सीनियर डिवीजन वेतनमान में) की निरन्तरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-48/लो०से०अधि०/देहरादून दिनांक 02-02-2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-168/XXXVI(1)/2011-326/2011 दिनांक 01-09-2011 द्वारा पुर्नजीवित/सृजित संयुक्त निबन्धक का 01 पद की निरन्तरता वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये, दिनांक 01-03-2013 से 28-02-2014 तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-04-लोक सेवा अधिकरण-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-1270/76-दस, दिनांक 20-07-1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-877/दस-92-24(8)/92 दिनांक 07-11-1992 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डी० पी० गैरोला)

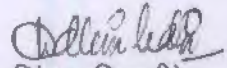
प्रमुख सचिव

संख्या- 59 (1) / XXXVI(1)/2013-326/2001 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरोय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 3- वित्त अनुभाग-5/कार्मिक अनुभाग/एन०आई०सी०/गार्डबुक।

आज्ञा से,


(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव